

भारत के तटीय पारस्थितिकी तंत्र का संरक्षण

प्रलिस के लिये:

CAG, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तटीय वनियमन क्षेत्र अधिसूचना, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी

मेन्स के लिये:

भारत के तटीय पारस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [नयित्क और महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) ने संसद में एक रपिर्ट पेश किया कि क्या भारत के तटीय पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम सफल रहे हैं।

- इस नवीनतम रपिर्ट में वर्ष 2015-20 से तटीय पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के ऑडिट के अवलोकन शामिल हैं।

नयित्क और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लेखापरीक्षा

- CAG के पास सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की जाँच और रपिर्ट करने का संवैधानिक अधिकार है।
- CAG ने "पूर्व-लेखापरीक्षा अध्ययन" किया और पाया कि तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तटीय वनियमन क्षेत्र (CRZ) का उल्लंघन हुआ था।
 - उच्च ज्वार सीमा (HTL) से 500 मीटर तक की तटीय भूमि और खाड़ियों, लैगून, मुहाना, बैकवाटर और नदियों के किनारे 100 मीटर के क्षेत्र को ज्वारीय उतार-चढ़ाव के अधीन तटीय वनियमन क्षेत्र (CRZ) कहा जाता है।
- मीडिया ने अवैध निर्माण गतिविधियों (समुद्र तट की जगह को कम करने) और स्थानीय निकायों, उद्योगों और जलीय कृषि फार्मों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट की घटनाओं की सूचना दी, जिससे वित्त जाँच हुई।

समुद्र तट के संरक्षण हेतु केंद्र ज़िम्मेदार:

- परिचय:
 - सरकार ने विशेष रूप से निर्माण के संबंध में भारत के तटों पर गतिविधियों को वनियमन करने हेतु [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986](#) के तहत अधिसूचना जारी की है।
 - मंत्रालय द्वारा लागू [तटीय वनियमन क्षेत्र अधिसूचना \(CRZ\) 2019](#), बुनियादी ढाँचा गतिविधियों के प्रबंधन और उन्हें वनियमन करने के लिये तटीय क्षेत्र को वनियमन क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है।
 - CRZ के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार तीन संस्थान हैं:
 - केंद्र में राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (NCZMA)
 - प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में राज्य / केंद्रशासित प्रदेश तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMAs / UTCZMAs) और
 - प्रत्येक ज़िले में ज़िला स्तरीय समिति (DLCs) जिसमें तटीय क्षेत्र है और जहाँ CRZ अधिसूचना लागू है।
- निकायों की भूमिका:
 - ये निकाय जाँच करते हैं कि क्या सरकार द्वारा दी गई CRZ मंजूरी प्रक्रिया के अनुसार है, क्या डेवलपर्स परियोजना को आगे बढ़ने के लिये शर्तों का पालन कर रहे हैं, और क्या [एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम \(ICZMP\)](#) के तहत परियोजना विकास के उद्देश्य सफल हैं।
 - वे [सतत विकास लक्ष्यों](#) के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की दशा में सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का भी मूल्यांकन करते हैं।

लेखापरीक्षा परणाम:

- **NCZMA स्थायी नकियाय के रूप में :**
 - पर्यावरण मंत्रालय ने NCZMA को स्थायी नकियाय के रूप में अधिसूचित नहीं किया था तथा इसे प्रत्येक कुछ वर्षों में पुनर्गठित किया जाता रहा था ।
 - परभाषित सदस्यता के अभाव में यह एक तदर्थ नकियाय के रूप में कार्य कर रहा था ।
- **वर्षिषज्ज मूल्यांकन समतियों की भूमिका:**
 - परयोजना संबंधी वचिर-वमिरश के दौरान वर्षिषज्ज मूल्यांकन समतियों के मौजूद नहीं थे ।
 - EAC वैज्ञानिक वर्षिषज्जों और वरषिठ नौकरशाहों की एक समति है जो एक बुनयिदी ढाँचा परयोजना की व्यवहार्यता और इसके पर्यावरणीय परणामों का मूल्यांकन करती है ।
 - वचिर-वमिरश के दौरान EAC के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से भी कम होने के उदाहरण थे ।
- **SCZMA का गठन नहीं किया गया:**
 - राज्य स्तर पर जहाँ राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (SCZMA) नरिणय लेते हैं, केंद्रीय लेखा परीक्षक ने उन उदाहरणों का अवलोकन किया जहाँ SCZMA ने संबंधित अधिकारियों को परयोजनाओं की सफिरशि कयि बुना स्वयं ही मंजूरी दे दी थी ।
 - इसके अलावा SCZMA ने अनविरय दसतावेज प्रस्तुत कयि बुना कई परयोजनाओं की सफिरशि की थी ।
- **अपर्याप्तता के बावजूद परयोजनाओं की स्वीकृति:**
 - **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)** रपिरट में अपर्याप्तता के बावजूद परयोजनाओं को मंजूरी दयि जाने के उदाहरण थे ।
 - इनमें गैर-मान्यता प्राप्त सलाहकार शामिल थे जो EIA रपिरट तैयार कर रहे थे, पुराने डेटा का उपयोग कर रहे थे, परयोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे, उन आपदाओं का मूल्यांकन नहीं कर रहे थे जनिसे परयोजना क्षेत्र प्रभावति था ।

राज्यों में समस्याएँ:

- **मन्नार की खाड़ी** द्वीप समूह के संरक्षण के लयि तमलिनाडु के पास कोई रणनीति नहीं थी ।
- गोवा में प्रवाल भित्तियों की नगिरानी के लयि कोई व्यवस्था नहीं थी और कछुओं के नेस्टिंग स्थलों के शकिार से संरक्षण के लयि कोई प्रबंधन योजना नहीं थी ।
- गुजरात में कच्छ की खाड़ी के जड़त्वीय क्षेत्र की मटिटी और पानी के भौतिक रासायनिक मापदंडों का अध्ययन करने के लयि खरीदे गए उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था ।
- ओडिशा के केंद्रपाड़ा में **गहरिमाथा अभयारण्य** में समुद्री गश्त नहीं हुई ।

तटीय प्रबंधन के लयि भारतीय पहल:

- **सतत् तटीय प्रबंधन के लयि राषट्रीय केंद्र:**
 - इसका उद्देश्य पारंपरिक तटीय और द्वीपीय समुदायों के लाभ और कल्याण के लयि भारत में तटीय और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत एवं स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना है ।
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना:**
 - यह स्थरिता प्राप्त करने के प्रयास में भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं सहति तटीय क्षेत्र के सभी पहलुओं के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके तट के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है ।
- **तटीय वनियमन क्षेत्र:**
 - CRZ को 'पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (जसिका नाम अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दयि गया है) द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचित किया गया था ।

आगे की राह:

- इन रपिरटों को संसद की स्थायी समतियों के समक्ष रखा जाता है, जो उन नषिकर्षों और अनुशंसाओं का चयन करती हैं जनिहें वे जनहति के लयि सबसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उन पर सुनवाई की व्यवस्था करते हैं ।
- इस मामले में, पर्यावरण मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कविह CAG द्वारा बताई गई खामियों की व्याख्या करे और उसमें संशोधन करें ।

नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि

1. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीतिका वविरण प्रदान करे ।
2. वह वभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या वसिर्जन के मानक नरिधारति करे ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जारी की गई थी।
- EIA, परियोजना के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन के लिये प्रदान किया जाता है।
- EIA के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक किसी भी विकासात्मक परियोजना पर जन सुनवाई और जन भागीदारी की प्रक्रिया है।
- हालाँकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 में कहीं भी पर्यावरण संरक्षण के लिये सार्वजनिक भागीदारी का उल्लेख नहीं है। यह पर्यावरण की रक्षा के लिये केवल सरकारी अधिकारियों और प्रदूषकों से संबंधित है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- EPA, वर्ष 1986 केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिये सभी उचित उपाय करने और पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रभावी मशीनरी स्थापित करने का अधिकार देता है।
- EPA की 1986 की धारा 3, केंद्र सरकार को ऐसे स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन की गुणवत्ता या संरचना के संबंध में विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये मानक निर्धारित करने का अधिकार देती है। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः विकल्प (b) सही है।

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/conserving-india-s-coastal-ecosystems>

